

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्या:-309/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/389)

1. शंकर गुर्जर उम्र 23 वर्ष पुत्र लीलाराम निवासी भोज्याला का गुवाडा तहसील टहला जिला अलवर।

---अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलेक्टर, अलवर, राजस्थान।
2. तहसीलदार टहला जिला अलवर।

---रेस्पॉण्डेन्ट्स

उपस्थिति:-

1. श्री महेन्द्र शर्मा व महेश चन्द गौतम एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पॉण्डेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.05.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ग्राम भोज्याला का गुवाडा घेवर तहसील टहला जिला अलवर का बीपीएल श्रेणी का भूमिहीन व्यक्ति है तथा अपीलार्थी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि कार्य हेतु भू आवंटन) नियम 1970 की धारा 8 के तहत भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया जिस पर अपीलान्ट को ग्राम घेवर तहसील टहला जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 1.50 हैक्टर किस्म बंजड़ में से 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.38 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में से सम्पूर्ण रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 322 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में से सम्पूर्ण रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 678/320 रकबा 0.6150 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में से 0.10 हैक्टर कुल 1.13 हैक्टर सिवायचक भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा अपने आवंटन आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/2237 दिनांक 02.03.2022 को किया गया एवं आवंटित भूमि का कब्जा अपीलान्ट को संभला दिये जाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी इत्यादि में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा आवंटित भूमि पर पैसे लगाकर एवं कड़ी मेहनत कर भूमि को कृषि योग्य तैयार किया गया एवं अपीलार्थी आवंटित भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। उन्होंने आगे कथन किया है कि आवंटन के पश्चात् अपीलान्ट को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) एवं प्रभारी जॉच कमेटी अलवर की जॉच रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत कराया है कि प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के दौरान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत किये गये आवंटन को गठित जिला

P.T.O

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्तरीय जॉच दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है। जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी के द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काशत है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काशत की जा रही है। उक्त आवंटित भूमि वन विभाग, खनिज विभाग से सम्बन्धित नहीं है तथा अपीलान्त भूमिहीन व गरीब बीपीएल परिवार की श्रेणी में आता है। आवंटी, आवंटन नियमों की समस्त शर्तों की पालना करता चला आ रहा है, उसके बावजूद अधीनस्थ जिला कलेक्टर अलवर द्वारा अपीलार्थी के जवाब को बिना कन्सीडर किये ही एवं अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने का अधिकार नहीं देकर एवं न्यायिक प्रक्रिया व विधि के प्रावधानों की बिना पालना किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2023 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को अपास्त कर दिया गया, जो आदेश विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त का परिवार बहुत ही गरीब बीपीएल श्रेणी का है और सिर्फ खेती पर ही निर्भर है तथा अपीलार्थी द्वारा भूमि आवंटन हेतु किसी तरह का कोई छल-कपट नहीं किया गया है और अपीलार्थी द्वारा भू आवंटन नियम की किसी भी शर्त का उल्लंघन भी नहीं किया गया है तथा अपीलार्थी राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन) 1970 की समस्त शर्तों हेतु पात्रता रखता है और इसीलिये आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं नियमों की पूर्णतय पालना करते हुए ही अपीलार्थी को भूमि आवंटन हेतु पात्र मानते हुए ही विधि सम्मत आवंटन किया गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक दृष्टिगण के व भू आवंटन नियम 1970 के विधिक प्रावधानों पर बिना गौर किये ही एवं वास्तविकता की बिना कोई जॉच किये ही केवल एकतरफा की गई फौरी जॉच को ही आधार बनाकर आवंटन आदेश को निरस्त किया गया है, जो निर्णय विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2023 को निरस्त फरमाया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 02.03.2022 को बहाल किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जॉच किये जाने हेतु जिला कलेक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जॉच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जॉच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय अलवर ने विस्तृत जॉच की जाकर जॉच रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की

(3) अभिशंषा की गई है। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटीकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2023 में निम्न तथ्यों व रिपोर्ट का अंकन किया गया है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडों की पालना नहीं की है, आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका में संधारित है या नहीं से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उद्घोषणा जारी होने के पश्चात् तामील/चस्पानगी के सम्बन्ध में तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न नहीं है, आवंटन सलाहकार समिति की बैठक सूचना की तामील कब हुई, इस सम्बन्ध में पत्रावली में तारीख का अंकन नहीं है, ना ही तामील कुलिन्दा की रिपोर्ट अंकित है, पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं है एवं वन विभाग खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है साथ ही आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर नहीं है, हाल व साबिक रिकार्ड संलग्न नहीं है, आवेदन पत्र पर सक्षम अधिकारी की मार्किंग नहीं है, प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटीकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है, जॉच कमेटी ने आवंटन आदेश शिविरों/फैलोअप कैम्पों में नहीं किया जाना बतलाया गया है, पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नहीं है, पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उक्त आवंटन के सम्बन्ध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 के अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा भी की गई है, इत्यादि जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2023 पारित किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2023 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक

P.T.O

अधीनस्थ न्यायालय अलवर
अधीनस्थ न्यायालय अलवर

(4)

21.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसा म अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति-संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति-संभागीय आयुक्त,
जयपुर।